an>

Title: Need to protect the interests of public sector oil companies.

श्री राजीव सातव (हिंगोली)ः सरकार द्वारा चालित तेल कंपनियां आधुनिक भारत की विरासत है और मुनाफे में है इसलिए इन्हें 'नवरत्न' के नाम से नवाजा जाता है। यह कंपनियां आज भी भारत के 95 प्रतिशत जरूरतों को पूरा करती हैं, यह इन कंपनियों के समर्पित कर्मचारियों के लगन की देन है।

आज ऐसे दिन आ गए हैं कि यह सरकार या तो निजी कंपनियों के पक्ष में नीतियां बना रही है या फिर भारत के नवरत्नों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की तैयारी में है। इससे आवश्यक वस्तुओं के दामों का नियंत्रण भारतवासियों के हाथ से निलकर निजी कंपनियों के हाथ में चला जायेगा। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

एक साल पहले केन्द्र सरकार ने सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंप के विक्रेता के चयन के लिए विज्ञापन निकाला था। आज एक साल बाद भी सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंप के विक्रताओं का चयन नहीं हो पाया है, परन्तु निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप का आबंटन जारी है। निजी कंपनियों की तरक्की भी होनी चाहिए। उन्हें भी पेट्रोल पंप लगाने चाहिए। पर क्या उनके मुनाफे के लिए सरकारी कंपनियों को घाटे में धकेल देना ठीक है? अगर हमारी सरकारों के पास ऊर्जा और ईंधन की कमान ही नहीं रह जाएगी तो भारत का विकास कैसे सुनिश्चित होगा?

मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में कितने Letter of Intents (LOIs) IOC/BPC/HPC/ESSAR/Reliance Industries Ltd and SHELL द्वारा ईश्यू किए गये? सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंप के विक्रेता चयन पर रोक क्यों लगी हुई है? एवं भारत सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि नवरत्न कंपनियां का मार्केट शेयर और मुनाफा न घटे।